अवध की आवाज

www.avadhkaawaz.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित

वर्ष–10 अंक–263 R.N.I.- UPHIN/2012/45127 लखनऊ बुधवार 22 दिसम्बर 2021 पृष्ठ – 8 मूल्य–3 रूपया

संक्षिप्त समाचार

दुख की घड़ी में दुख संवेदना व्यक्त करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष मा0 हृदय नारायण दीक्षित

उन्नाव। सोमवार को पत्रकार अविनाश बाजपेई के भाई कि अचानक तबीयत खराब हो गई परिवारी जन आनन फानन यथोचित अस्पताल लेकर के गए परंतु पत्रकार के भाई बबुआ बाजपेई को बचा नहीं सके इस

दुख की घड़ी में दुख संवेदना व्यक्त करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष मा0 हृदय नारायण दीक्षित साथ में हिलौली ब्लाक के ब्लाक प्रमुख दिलीप दीक्षित भाजपा वरिष्ठ नेता अरुण दीक्षित भाजपा जिला उपाध्यक्ष आनंद अवस्थी व भाजपा के पदाधिकारी सहित काफी भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित होकर दुख संवेदना प्रकट किया। वहीं पर पत्रकार सुरक्षा महासमिति के प्रदेश उपाध्यक्ष गुड्डू मिश्रा अपनी अवध की आवाज टीम सहित पहुंचकर दुख संवेदना व्यक्त किया।

ग्राम पंचायत टडई खुर्द में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुआरोग्य मेले का आयोजन

अवध की आवाज

सिधौली–सीतापुर।सिधौली तहसील एवं ब्लाक के ग्राम पंचायत टडई खुर्द में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुआरोग्य मेले का आयोजन किया गया।मनोज गौ सेवा वाला के द्वारा गौ पूजन एवं फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया गया इस अवसर पर उपस्थित ग्राम प्रधान शिवकुमार यादव ,डॉ ज्ञानेंद्र सिंह, डॉ अनिल वर्मा ,डॉ नम्रता शुक्ला, पशुधन प्रसार अधिकारी सोहनलाल पांडे , अवधेश कुमार अशोक कुमार व रामनाथ पंकज सिंह लालजी यादव यशार्थ श्रीवास्तव यशू ड्राइवर मनोज कुमार काफी संख्या में ग्रामीण गोपालक आदि उपस्थित रहे।

फल फूल रहा है अवैध रूप से कच्ची देसी शराब, का धंधा

अवध की आवाज ब्यूरो

गोंडा। थाना मोतीगंज से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ग्रामसभा पड़ता है खिराई खिरवा के मजरा पिपरा सूर्यमणि में दिनदहाड़े अर्थात शाम ढलते ही अवैध रूप से दारू की होती है बिक्री गांव अर्थात कई गांव के लोग शाम से ही मजरा पिपरा सूर्यमणि में घुस जाते हैं और दारु पीने के पश्चात आपस में गाली गलौज करते हुए अपने अपने रास्ते बढ़ बढ़ाते हुए लड़ते हुए निकल जाते हैं यह प्रक्रिया शाम लगभग 5रू30 बजे के बाद से प्रारंभ होती है इस तरह से जबकि एसपी गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया था।

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, एकल खिड़की मंजूरी से नए साल में बढ़ेगी एफडीआई आवक

एजेंसी

नयी दिल्ली। कारोबारी सुगमता को बढ़ाने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को उदार बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों से भारत को इस साल अब तक रिकॉर्ड एफडीआई हासिल करने में मदद मिली है और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, एकल खिड़की मंजूरी और जीआईएस मानचित्रित भूमि जैसे उपायों से इसमें 2022 के दौरान और बढ़ोतरी की उम्मीद है। वैश्विक मंदी और कोविड–19 महामारी के बावजूद भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 2020–21 में बढ़कर 81.72 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।चालू वित्त वर्ष में अप्रैल–जुलाई के दौरान देश में एफडीआई 62 प्रतिशत बढ़कर 27.37 अरब डॉलर हो गया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में सचिव ने कहा अनुराग जैन ने पीटीआई–को बताया, ''बढ़ता एफडीआई भारत की वृद्धि गाथा में वैश्विक विश्वास को दर्शाता है।

दुनिया भरोसेमंद साझेदार चाहती है। भारत वृद्धि के वे सभी मानदंड मुहैया कर रहा है, जो निवेशक निवेश से पहले देखना चाहेंगे।'' उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी), एकल खिड़की मंजूरी और जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) मानचित्रित भूमि बैंक जैसे कदमों से आगे निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी।'' उन्होंने कहा कि सरकार कारोबारी सुगमता के लिए चौतरफा कोशिश कर रही है और पिछले कुछ वर्षों में 25,000 से अधिक अनुपालनों में सरलता आई है।जैन ने कहा, ''संरचनात्मक सुधार और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों, स्टार्टअप कार्यक्रम और एफडीआई नीति के उदारीकरण से औद्योगिक परिदृश्य में आमूलचूल बदलाव आ रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि स्टार्टअप परिवेश का समर्थन करने के लिए केंद्र के प्रयासों के चलते भारत की दुनिया भर के व्यापार और निवेश क्षेत्र में चर्चा है। उन्होंने कहा कि अब तक केंद्र सरकार के 19 मंत्रालय ध् विभाग और 10 राज्य राष्ट्रीय एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली में शामिल हो चुके हैं।इसी तरह भारत औद्योगिक भूमि बैंक जीआईएस सक्षम है और इसके तहत 4,500 से अधिक औद्योगिक पार्कों की मैपिंग की गई है तथा निवेश के लिए उपलब्ध खाली औद्योगिक भूखंडों को ऑनलाइन देखा जा सकता है। सरकार ने कई क्षेत्रों में कोयला खनन, रक्षा उत्पादन, अनुबंध विनिर्माण और एकल–ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई नियमों में ढील दी है।

स्थाई एवं अस्थाई रैन बसेरों तथा अलाव की व्यवस्था का किया निरीक्षण

सीतापुर। (सू0वि0) शीतलहर के दृष्टिगत जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने सोमवार की रात शहर के विभिन्न स्थलों पर स्थाई एवं अस्थाई रैन बसेरों तथा अलाव की व्यवस्था का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने रोडवेज बस स्टैंड, रोडवेज चौराहा, जिला चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय आदि स्थलों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कजियारा स्थित स्थायी शेल्टर होम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जरूरतमंदों को कम्बल भी वितरित किए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने भीषण ठंड एवं शीतलहर के दृष्टिगत आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित करने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि स्थायी शेल्टर होम की सूचना रोडवेज बस स्टैंड, जिला चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय आदि प्रमुख स्थलों पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाय। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि रात्रि के समय खुले मे रुके लोगों को रैन बसेरा के विषय मे अवगत कराते हुए रैन बसेरा तक ले जाने के भी प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने खुले में रुके व्यक्तियों को रैन बसेरा के निरूशुल्क प्रबन्ध के विषय में जानकारी दी तथा उन्हें रैन बसेरा मे ही रात्रि विश्राम के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों

को निर्देश दिए कि ऐसे व्यक्तियों को रैन बसेरा तक भेजने हेतु तत्काल प्रबन्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। सभी व्यवस्थाओं की नियमित रूप से निगरानी किए जाने के भी निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने विभिन्न स्थलों पर बनाए गए रैन बसेरों की क्षमता में वृद्धि किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने रैन बसेरों में रुके व्यक्तियों से व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी सदर अनिल कुमार, तहसीलदार सदर ज्ञानेन्द्र द्विवेदी, नायब तहसीदार सदर सुखवीर सिंह सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।

सरकार बनने पर तीन महीने के अंदर कराएंगे जाति आधारित जनगणना : अखिलेश

मैनपुरी। (उत्तर प्रदेश), 21 दिसंबर (वेब वार्ता)। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर तीन महीने के अंदर जाति आधारित जनगणना कराकर आबादी के हिसाब से सभी को हक और सम्मान दिया जाएगा। अखिलेश ने सीबीआई, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को 'भाजपा के प्रकोष्ठ' करार दिया और यह भी दावा किया कि सपा को मिल रहे जनसमर्थन से घबराई भाजपा ने उसके मुकाबले अपने छह रथ मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन वे सपा के रथ को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने यहां 'समाजवादी विजय रथ यात्रा' के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, ष्हम और आप पर आरोप लगता है कि हम किसी का हक छीन रहे हैं, लेकिन जातीय जनगणना से सब कुछ साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर तीन महीने के अंदर जातीय जनगणना की जाएगी और आबादी के हिसाब से सभी को हक और सम्मान दिया जाएगा। जनता जानती है कि हमने जो भी वादे किए उन्हें पूरा किया है। अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा, ष्जैसे ही हमने उनकी पार्टी को साथ लिया, तो दिल्ली से भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ, सीबीआई प्रकोष्ठ और ईडी प्रकोष्ठ सक्रिय हो गए। अब जैसे–जैसे चुनाव करीब आएगा

और भाजपा को हार का डर सताएगा तब यह दिल्ली वाले उत्तर प्रदेश में और भी ज्यादा आएंगे। अखिलेश का इशारा पिछले दिनों अपने कुछ करीबी सहयोगियों के यहां आयकर विभाग के छापों की तरफ था। उन्होंने भाजपा द्वारा उत्तर प्रदेश के छह स्थानों से जन विश्वास यात्रा शुरू किए जाने पर तंज करते हुए कहा, ष्जनता ने जब से सपा की रथ यात्रा को जोरदार समर्थन देना शुरू किया है तब से भाजपा को घबराहट होने लगी है। उसी का नतीजा है कि सपा के एक रथ के मुकाबले भाजपा के छह रथ निकल रहे हैं। मगर हमारा एक रथ उन सभी पर भारी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर सरकारी धन खर्च करके रैलियां आयोजित कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की रैली जनता की नहीं होती बल्कि सरकारी रैली होती है और उस पर सरकारी धन खर्च किया जाता है। यहां सपा की जो रैली हो रही है उसमें विशाल संख्या में आए लोग अपने संसाधनों से पहुंचे हैं। अखिलेश ने नौजवानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनका भविष्य सिर्फ सपा की सरकार में ही सुरक्षित है। उन्होंने कहा, ष्हम भरोसा दिलाते हैं। चाहे वह हमारे शिक्षामित्र हों, बीएड वाले या बीपीएड वाले हों, सपा की सरकार बनने पर हम सभी की मदद करेंगे। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो हमने शिक्षामित्रों को सम्मान दिया था। अगर कोई आपकी समस्या का समाधान कर सकता है तो वह समाजवादी पार्टी की सरकार ही है। सपा अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर अपनी कुछ खास कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरी भरने में मशगूल है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा ष्योगी सिर्फ नाम बदलने, रंग बदलने, शिलान्यास का शिलान्यास और उद्घाटन का उद्घाटन करने में ही उपयोगी हैं। मुख्यमंत्री लाल रंग से घबरा रहे हैं। लाल रंग क्रांति का और भावनाओं का रंग है, एक रंगी लोग इन भावनाओं को नहीं जानते। वह यह भी नहीं जानते कि हमारे आपके खून का रंग भी एक ही है। अखिलेश ने कहा कि संगीन मुकदमों में आरोपी योगी आदित्यनाथ देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने ऊपर दर्ज मुकदमे खुद ही वापस ले लिए। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में आयोजित इस रैली के मुख्य बैनर में अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव की तस्वीर भी नजर आई। रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ–साथ शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

औषधियों की नियमित जांच करें, व्यापारी बिल और कैश मेमो उपभोक्ताओं को अवश्य दें-अपर जिलाधिकारी

अवध की आवाज

हरदोई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग हरदोई की जिला स्तरीय कमेटी की बैठके अपर

जिलाधिकारी वंदना त्रिवेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में समिति के सदस्यों ने मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री के रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी ने खाद्य विभाग को निर्देशित किया कि दूध पनीर खाद्य तेल मसाले पर प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करें तथा औषधि विभाग को निर्देशित किया कि औषधियों की नियमित जांच करें। साथ ही व्यापारियों को निर्देश दिया कि बिल और कैश मेमो उपभोक्ताओं को अवश्य दें। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम एवं नियमों का पालन करते हुए खाद्य कारोबार करें। अभिहित अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि ईट राइट प्रोग्राम के अंतर्गत विद्यालय कैंपस एवं मंदिर को लाया जा रहा है। क्लीन स्ट्रीट फूड हब एवं फ्रेश वेजिटेबल फूड मार्केट हेतु खाद्य कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ विद्यालयों मैं बच्चों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी अभिहित अधिकारी मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी जिला खाद्य विपणन अधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व्यापार मंडल प्रतिनिधि पवन जैन प्रदीप गुप्ता बालकृष्ण गुप्ता एनके मुखर्जी आदि मौजूद रहे।

भारत सरकार को सम्बोधित पोस्टकार्ड निबन्ध प्रतियोगिता का किया गया आयोजन

अवध की आवाज ब्यूरो

गोंडा । देश भर में मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव

अभियान के तहत भारतीय डाक विभाग द्वारा देश भर में भारत के प्रधान मंत्री को सम्बोधित पोस्ट निबन्ध प्रतियोगिता की शुरुवात की गयी है। इसी के तहत सोमवार को धानेपुर क्षेत्र के बालिका इंटर कालेज में पोस्टकार्ड निबन्ध प्रतियोगिता का संचालन किया गया, जिसमे विद्यालय के बच्चों से अति संक्षिप्त शब्दों में निबन्ध लिखवाया गया सभी निबन्ध पत्रों को संकलित करके पैकेट के रूप में डाक विभाग द्वारा तय शुदा पते पर प्रेषित किया जाएगा जहां उच्च लेखनी वाले छात्रों को चयनित किया जाएगा, निबन्ध में बच्चों को देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण देने वाले उन वीर बलिदानियों का नाम उजागर करना है जिन्हें प्रमुखता नही दी गयी है साथ ही कल्पना भाषित करना है की 2047 में मनाया जाने वाला आजादी महोत्सव कैसा होगा इस पर आधारित निबन्ध छात्राओं द्वारा लिखे गए हैं इस प्रतियोगिता में सैकड़ों छात्राओं ने हिस्सा लिया, इस मौके पर जी. डी.एस. कर्मचारी संघ के वरिष्ट पदाधिकारी रामानन्द तिवारी सहित विद्यालय का स्टाप उपस्थित रहा।

ईवीएम/वीवी पैट की बारीकियों को भली–भांति समझ लें– ए0डी0एम0

अवध की आवाज

हरदोई। आगामी 2022 में होने वाले विधान सभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपंन कराने हेतु ईवीएमध् वीवी पैट प्रशिक्षण स्थानीय प्रेक्षागृह में उप जिला निर्वाचन अधिकारीध्अपर जिलाधिकारी वन्दना त्रिवेदी की उपस्थित में सामान्य मास्टर ट्रेनरों को दिया गया। प्रशिक्षण में अपर जिलाधिकारी ने सामान्य ट्रेनर्स से कहा कि ईवीएमध् वीवी पैट की बारीकियों को भली–भांति समझ लें ताकि निर्वाचन के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि न हो औरे निर्वाचन सकुशल सम्पन्न हों। प्रशिक्षण की प्रथम पाली प्रातः 11 से 1 बजे तक में विधान सभा सवायजपुर, शाहाबाद, सदर तथा गोपामऊ के सामान्य मास्टर ट्रेनरों को तथा द्वितीय पाली अपरान्ह 2 से 4 बजे में विधान सभा साण्डी, बिलग्राम–मल्लावां, बालामऊ एवं सण्डीला के सामान्य मास्टर टेनरों को मास्टर ट्रेनर/सहायक अभियंता डीआरडीए राजेश सिंह आदि ने ईवीएमध्वीवी पैट के सम्बन्ध में विस्तार से प्रशिक्षण देकर सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार, सहायक निर्वाचन अधिकारी बीएल भार्गव आदि उपस्थित रहें।

गौशालाओं में भूसा-चारा पर्याप्त मात्रा में रखा जाए:-जिलाधिकारी

अवध की आवाज

हरदाई। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में जनपद के सभी उपजिलाधिकारियों व अधिशासी अधिकारियों की बैठक हुई। उन्होंने निर्देश दिए कि एमआरएफ सेंटरों का कार्य जल्द पूरा किया जाए। उप जिलाधकारी निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते रहें। बैठक में अधिशासी अधिकारियों से भूमि विवादों के निस्तारण की स्थिति की जानकारी ली गयी तथा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तालाबो में एसटीपी लगाने का कार्य किया जाए। सभी गौशालाओं में भूसा–चारा पर्याप्त मात्रा में रखा जाए।पीओ डूडा को निर्देश दिया कि पीएम आवास योजना के आवासों का निर्माण तेजी से कराकर आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राना, अपर जिलाधिकारी वंदना त्रिवेदी, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार, पीओ डूडा, समस्त उपजिलाधकारी व अधिशासी अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मंगलवार को खुशहाल परिवार दिवस मनाया गया

अवधकी आवाज

हरदोई। जनपद के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मंगलवार को खुशहाल परिवार दिवस का आयोजन किया गया। जिला महिला अस्पताल में खुशहाल परिवार दिवस का उद्घाटन परिवार कल्याण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और अपर मुख्य चिकित्स अधिकारी डा. सुशील कुमार ने किया। इस मौके पर नोडल अधिकारी ने कहा–दो ही बच्चे–सबसे अच्छे" यह नारा सभी को आत्मसात कर लेना चाहिए कि अपने और अपने परिवार की खुशी दो ही बच्चों में निहित है। इससे न केवल परिवार फलेगा फूलेगा बल्कि देश की उन्नति में भी सहायक होगा। हमारे पास संसाधन सीमित है द्य इसलिए उन संसाधनों का समुचित उपयोग तभी हो पाएगा जब जनसंख्या नियोजित होगी । सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जनसमुदाय को छोटा परिवार सुखी परिवार हेतु जागरूक करें।जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी प्रेमचंद यादव ने बताया। इस मौके पर जिला महिला अस्पताल में 26 प्रसव हुए द्य एक महिला ने नसबंदी अपनाई द्य 10 महिलाओं ने प्रसव पश्चात आई यू सी डी, 6 महिलाओं ने आई यू सी डी लगवाई और एक महिला ने गर्भपात उपरांत आई यू सी डी लगवाई। इसके अलावा त्रैमासि क गर्भनिरोधक इंजेक्शन अन्तरा 199 महिलाओं ने अपनाया। 66 पैकेट्स गर्भनिरोधक गोली छाया, माला एन के 59 पैकेट्स, आकस्मिक गर्भनिरोधक गोलियां 5 और कुल 1650 कंडोम का वितरण निःशुल्क किया गया। इस अवसर पर बाल रोग विशेषज्ञ डा. वी.के.गुप्ता, डा. रूपल, डा. आशा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुजीत कुमार , उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई के जिला परिवार नियोजन विशेषज्ञ, परिवार नियोजन लाजिस्टिक मैनेजर किन्दरलाल, परिवार कल्याण परामर्शदाता गरिमा शुक्ला और आईपास संस्था से रागिनी श्रीवास्तव

सम्पादकीय

नीलमणि फूकन और दामोदर मौउजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार

पिछले दिनों वर्ष 2020 और 2021 के लिए भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाले भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 'ज्ञानपीठ पुरस्कार' की घोषणा की गई।

56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार क्रमशः 88 वर्षीय नीलमणि फूकन जूनियर और 77 वर्षीय दामोदर मौउजो को दिया जाएगा, जिनके नाम का चयन भारतीय साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के आधार पर किया गया।

नीलमणि फूकन जूनियर प्रख्यात असमिया कवि हैं तथा दामोदर मौउजो कोंकणी उपन्यासकार हैं। दोनों ही साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं तथा संबंधित क्षेत्रीय साहित्य में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। 2020 और 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कारों को लेकर अंतिम निर्णय प्रसिद्ध कथाकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा राय की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में लिया गया।

ज्ञानपीठ पुरस्कार के चयन की प्रक्रिया काफी जटिल है, जो कई महीनों तक चलती है। किसी भी लेखक को साहित्य की आजीवन सेवा और साहित्य जगत में उसके अहम योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 1961 में स्थापित यह पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, जो किसी भी लेखक को मरणोपरांत नहीं दिया जाता।

10 सितम्बर 1933 को असम के दरगांव में जन्मे नीलमणि फूकन असमिया भाषा में कविता की 13 पुस्तकें लिख चुके हैं। असमिया साहित्य की अन्य विधाओं पर भी उन्होंने बहुत काम किया है। असमिया साहित्य में उन्हें ऋषि तुल्य माना जाता है। असमिया साहित्य में विशेष स्थान रखने वाले नीलमणि फूकन पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार, असम वैली अवार्ड तथा साहित्य अकादमी फैलोशिप सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। नीलमणि फूकन को साहित्य के प्रति उनकी आजीवन सेवाओं का सम्मान करते हुए सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है।

उन्हें यह सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान दिए जाने की घोषणा के साथ ही असम को अब तक के ज्ञानपीठ पुरस्कारों के इतिहास में तीसरी बार यह पुरस्कार हासिल करने का सुअवसर मिला है। नीलमणि फूकन से पहले 1979 में बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य और 2000 में इंदिरा गोस्वामी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

नीलमणि फूकन ने 1950 के दशक की शुरुआत से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था और 1961 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय से इतिहास में मास्टर डिग्री प्राप्त प्राप्त करने के बाद 1964 में गुवाहाटी में आर्य विद्यापीठ कॉलेज में व्याख्याता के रूप में कैरियर की शुरूआत की, जहां वे 1992 में अपनी सेवानिवृत्ति तक कार्यरत रहे। प्रगतिशील सोच वाले आधुनिक कवि नीलमणि फूकन करीब सात दशकों से कविता कर्म में सक्रिय हैं, जिन्होंने असमिया कविता को नया अंदाज प्रदान किया है। आत्मकथा और 13 कविता संग्रह के अलावा आलोचना पर भी उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में 'सूर्य हेनु नामी आहे ए नोडियेदी', 'गुलापी जमुर लग्न', 'कोबिता' इत्यादि प्रमुख रूप से शामिल हैं। उन्होंने जापान और यूरोप की कविताओं का असमिया में अनुवाद भी किया।

1981 में उन्हें उनके कविता संग्रह 'कोबिता' पर असमिया में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1997 में असम घाटी साहित्य पुरस्कार मिला था। 2002 में साहित्य अकादमी ने उन्हें अपना फैलो बनाया था, जो भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी द्वारा दिया गया सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। भारत सरकार द्वारा 1990 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा प्रतिष्ठित ब्रह्मपुत्र वैली पुरस्कार सहित उन्हें बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें 2019 में डी.लिट् से सम्मानित किया गया था।

1 अगस्त 1944 को दक्षिण गोवा में मजोरदा के तटीय गांव में एक गौड़ सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्मे दामोदर मौउजो कोंकणी भाषा के प्रमुख कवि, आलोचक, लघु कथाकार, उपन्यासकार और कोंकणी भाषा के विख्यात पटकथा लेखक हैं। करीब 50 वर्ष लंबे लेखन कैरियर में वे छह कहानी संग्रह, चार उपन्यास, दो आत्मकथात्मक कृतियां और बाल साहित्य को कलमबद्ध कर चुके हैं।

दामोदर मौउजो कोंकणी साहित्यिक परिदृश्य में चर्चित चेहरा हैं और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, गोवा कला अकादमी साहित्य पुरस्कार, कोंकणी भाषा मंडल साहित्य पुरस्कारों सहित कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है। 2011—12 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा उन्हें कोंकणी साहित्य के पूर्व और उत्तर औपनिवेशिक इतिहास पर परियोजना के लिए वरिष्ठ फैलोशिप से सम्मानित किया। दामोदर मौउजो को सुनामी साइमन तथा कारमेलिन जैसे उनके चर्चित उपन्यासों के अलावा गोवा की अन्य कहानियों के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है।

साहित्य अकादमी की वित्त समिति के सदस्य के अलावा कार्यकारी बोर्ड, सामान्य परिषद इत्यादि में कार्य कर चुके दामोदर मौउजो की प्राथमिक शिक्षा मराठी और पुर्तगाली भाषाओं में हुई थी जबकि उनकी माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी में हुई। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई के साथ—साथ परिवार की दुकान में चाचा की मदद की। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उन्होंने बी.कॉम की डिग्री हासिल की और उसी दौरान उन्होंने कोंकणी में लघुकथाएं लिखना शुरू किया था, जिन्हें पाठकों ने खूब सराहा और उनमें से कुछ का अंग्रेजी में अनुवाद और प्रकाशन भी किया गया। 1983 में उनके उपन्यास 'कार्मेलिन' के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2011 में उपन्यास 'सुनामी साइमन' के लिए विमला वी. पाई विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 'कार्मेलिन' उपन्यास फारस की खाड़ी के देशों में काम करने वाली घरेलू नौकरानी की पीड़ा और यौन शोषण से संबंधित है, जिसका असमिया, बंगाली, मैथिली, नेपाली, गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, तमिल, कन्नड़, हिन्दी और अंग्रेजी, 12 भाषाओं में अनुवाद किया गया। 'सुनामी साइमन' उपन्यास उन्होंने 1996 में तमिलनाडु के तट पर सुनामी आने के बाद लिखा था। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। 1971 में दामोदर मौउजो का पहला लघुकथा संग्रह 'गँथन' प्रकाशित हुआ, जिसके साथ उनके लेखन की शुरुआत हुई। 1975 में उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे का बदला लेने के बारे में एक उपन्यास 'सूद' लिखा, जिस पर 2006 में इसी शीर्षक से एक फिल्म भी बनी। अभी तक वह 2014 में 'सैपोन मोगी' सहित कुछ लघु कहानी संग्रह, 'कार्मेलिन' सहित कुछ उपन्यास लिख चुके हैं। पांच कोंकणी फिल्मों शितू, अलीशा, सूद, ओ मारिया और एनिमी के लिए भी उन्होंने पटकथा अथवा संवाद लिखे, जिनमें से गोवा फिल्म फेस्टिवल में उन्हें अलीशा के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार, शितू और ओ मारिया के लिए सर्वश्रेष्ठ संवाद पुरस्कार मिला।

शिक्षा सुधार है रोजगार की कुंजी

—भरत झुनझुनवाला—

केंद्र सरकार का कहना है 2018 में प्रोविडेंट फंड की सदस्यता लेने वाले श्रमिकों में 70 लाख की वशद्धि हुई है। लेकिन प्रोविडेंट फंड की सदस्यता में वशद्धि और रोजगार में वशद्धि दो अलग—अलग बाते हैं। 2018 का समय नोटबंदी और जीएसटी का था। इन नीतियों के कारण छोटे उद्योग कम हुए थे और बड़े उद्योग बढ़े थे। छोटे उद्योग ही ज्यादा रोजगार बनाते थे। इसलिए यदि छोटे उद्योगों में 100 कर्मी बेरोजगार हुए तो हम मान सकते हैं कि बड़े उद्योगों में 50 रोजगार बने होंगे। कुल रोजगार में 50 की गिरावट आई। लेकिन जिन 50 को रोजगार मिला, वे प्रोविडेंट फंड के सदस्य बने, चूंकि वे बड़े उद्योगों में कार्यरत थे। इसलिए प्रोविडेंट फंड की सदस्यता में 50 सदस्यों की वशद्धि हुई, जबकि साथ—साथ कुल रोजगार में 50 श्रमिकों की गिरावट आई। इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए सामयिक श्रम सर्वे में कहा गया कि 2012 एवं 2018 के बीच अपने देश में शहरी बेरोजगारी में तीन गुना वशद्धि हुई है। और गंभीर विषय यह है कि यदि मान भी लें कि 2018 में 70 लाख नए रोजगार बने तो भी बेरोजगारी की समस्या का निदान नहीं होता है क्योंकि अपने देश में हर वर्ष 120 लाख नए युवा श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से यदि 70 लाख को रोजगार मिल भी गए तो भी 50 लाख युवा बेरोजगार ही रह जाएंगे। समस्या के गंभीर होने के दूसरे संकेत उपलब्ध हैं।

केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए उपरोक्त सामयिक श्रम सर्वे के अनुसार 2012 से 2018 के बीच शहरी बेरोजगारी की दर में 3 गुना वृद्धि हुई है। इसी सर्वे के अनुसार 2018 में अपने देश में 15 से 24 वर्ष के लोगों में 28.5 प्रतिशत बेरोजगार थे जो कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अधिकतम था। इसी सर्वे के अनुसार 2012 से 2018 के बीच वेतन में भी गिरावट आई है। जैसे मान लीजिए आपका 2012 में वेतन 100 रुपए प्रति दिन था। वृद्धि हुई और 2018 में आपका वेतन 110 रुपए प्रति दिन हो गया। वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन मान लीजिए इसी अवधि में जो टॉफी 2012 में एक रुपए में मिलती थी वह 2018 में 1.50 रुपए में मिलने लगी। ऐसा हुआ तो आपके वास्तविक वेतन में कटौती हुई। 2012 में आप एक दिन के वेतन में 100 टॉफी खरीद सकते थे। 2018 में एक दिन के वेतन में आपको केवल 55 टॉफी मिलेंगी चूंकि वेतन में वृद्धि कम और टॉफी के दाम में वृद्धि ज्यादा हुई है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए सर्वे में कहा गया कि 2012 से 2018 के बीच वास्तविक वेतन में 1.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। अतः बेरोजगारी की समस्या को झुठलाने से काम नहीं चलेगा। इसके मूल कारणों का निवारण करना होगा। बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण तकनीकी बदलाव है। जैसे पूर्व में बैंक में खाते क्लर्कों द्वारा रखे जाते थे। अब यह कार्य कम्प्यूटर से होने लगा है। बैंक की कई शाखाओं में केवल दो या तीन कर्मी काम करते हैं। कम्प्यूटर ने श्रमिकों की जरूरत को कम कर दिया है। लेकिन साथ—साथ बैंकों का प्रसार बढ़ा है और शाखाओं की संख्या बढ़ी है। इनमें नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। इतिहास पर गौर करें तो किसी समय यातायात का प्रमुख साधन घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी। इसके बाद कार का आविष्कार हुआ जिसके कारण घोड़ा गाड़ी चलाने वाले बेरोजगार हो गए।

लेकिन कार के चलन का विस्तार हुआ। इनके उत्पादन और मरम्मत में नए रोजगार बने। इनके लिए सड़क और फ्लाईओवर बनाने में भी रोजगार बने। इसलिए घोड़ा गाड़ी में रोजगार में गिरावट के बावजूद यातायात क्षेत्र में कुल रोजगार बढ़े। वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा हमारे सामने है। तमाम कार्य जैसे हड्डी में फ्रैक्चर को पहचानना अथवा खून की जांच करना अब कम्प्यूटर द्वारा किए जाने लगे हैं। ऐसा होने से रेडियोलाजिस्ट और पैथोलाजिस्ट के रोजगार पर संकट आने को है। लेकिन जिस प्रकार घोड़ा गाड़ी के समाप्त होने के बावजूद कार के चलन से कुल रोजगार में वशद्धि हुई, उसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से तमाम नए उत्पाद बन सकते हैं, जैसे आपके मनपसंद प्लाट का सिनेमा बनाना अथवा वीडियो मिक्स करना इत्यादि। अतः हमें अपने युवाओं को रोजगारों की इन नई संभावनाओं को पकड़ने को प्रशिक्षित करना होगा। यहां प्रमुख समस्या हमारी शिक्षा व्यवस्था की है। वर्तमान में युवाओं का रुझान सरकारी नौकरियों की तरफ बना हुआ है, बावजूद इसके कि सरकारी नौकरियों की संख्या में कमी आई है। लेकिन सामान्य शिक्षा वाले प्राइमरी सरकारी स्कूल के टीचर को आज 50 से 70 हजार रुपए प्रति माह मिलते हैं, जबकि एक ट्रेंड नर्स अथवा डाटा इंट्री आपरेटर को बमुश्किल 15 हजार रुपए प्रति माह मिलते हैं। इसलिए युवाओं को नर्स अथवा डाटा इंट्री आपरेटर की क्षमता हासिल करने में रुचि नहीं है। उनका पूरा ध्यान सरकारी नौकरी हासिल करने की तरफ मात्र रहता है। वास्तविक 'शिक्षा' ग्रहण करने में उनकी रुचि नहीं है।

सरकार को चाहिए कि सरकारी कर्मियों और साधारण नागरिकों जैसे नर्स के वेतन के बीच संतुलन स्थापित करे जिससे सरकारी नौकरी का मोह कम हो और हमारे युवा सच्ची पढ़ाई पर ध्यान दें। इस दिशा में सरकार को प्राइमरी स्तर पर ही अंग्रेजी भाषा और कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए जिससे कि युवा आने वाले समय में कम्प्यूटर आधारित रोजगार जैसे पुस्तकों का अनुवाद करना अथवा वीडियो मिक्स करना जैसे कार्यों को स्वयं कर सकें और अपनी जीविका अर्जित कर सकें। हमें इस चिंता में नहीं रहना चाहिए कि अंग्रेजी को अपनाने से हमारी संस्कृति की हानि होगी। हमें ध्यान करना चाहिए कि किसी समय हमारी संस्कृति सिंधु घाटी की भाषा में समझी जाती थी। इसके बाद वही प्राकृत भाषा में परिवर्तित हुई और फिर देवनागरी में। लेकिन संस्कृति की निरंतरता कायम रही। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी संस्कृति का अंग्रेजीकरण करें जिससे कि हम अंग्रेजी भाषा में उत्पन्न होने वाले रोजगार भी हासिल करें और साथ—साथ अपनी संस्कृति का वैश्वीकरण भी कर सकें। यदि हम अपने वेद, पुराण तथा करपात्रीजी महाराज जैसे विद्वानों की टीकों को सुलभ अंग्रेजी में उपलब्ध करा दें तो हमारी संस्कृति का भी वैश्वीकरण होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए। इतिहास की उपयोगिता भविष्य को संवारने के लिए होती है। इतिहास का उद्देश्य इतिहास के कटघरे में जीवित रहने का नहीं होता है।

अगले जन्म मोहे गुरु न बनइयो, ओ राम जी

—जगदीश बाली—

हाल ही में समाचारपत्र में खबर पढ़ी कि हमीरपुर के एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक छात्र ने अध्यापक पर हाथ उठा दिया। यह पढ़ कर अपना विद्यार्थी जीवन याद हो आया। वाकई जमाना कितना बदल गया है! एक जमाना था कि स्कूल में की गई किसी शरारत के लिए शिक्षक तो सजा देते ही देते थे, पर साथ में माता—पिता भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे। परंतु बदलते वक्त के साथ गुरु—शिष्य के संबंधों में बहुत खटास और दूरी आ गई है। जिस देश में शिष्य अपने गुरु को देवतुल्य मानता आया है, वहीं आज इस रिश्ते में इतनी तल्खी और हिकारत आ गई है कि नौबत मारपीट तक ही नहीं, बल्कि कभी कत्ल तक भी पहुंच जाती है। कुछ वर्ष पहले दिल्ली के सुलतानपुरी इलाके के एक सरकारी स्कूल में अध्यापक का उसके ही शिष्य ने कत्ल कर दिया था।

यह घटना गुरु—शिष्य के बीच बिगड़ते रिश्ते की पराकाष्ठा है। दिसंबर 2014 में झारखंड के एक स्कूल के सातवीं कक्षा के तीन छात्रों ने अपने अध्यापक को इसलिए मार डाला क्योंकि उक्त अध्यापक ने उन्हें धूम्रपान न करने की सलाह दी थी। फरवरी 2012 में चेन्नई के एक स्कूल में नवीं कक्षा के छात्र ने चाकू से अपने अध्यापक की जान ले ली। हमारे प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं होती आई हैं। 14 दिसंबर 1998 में अरसू के एक सरकारी स्कूल के नवीं कक्षा के एक छात्र ने प्रधानाचार्य पर सरिए से वार किया जिसके कारण उनकी मौत हो गई। अगस्त 2014 में संजौली कॉलेज में छात्रों ने प्रधानाचार्य व अन्य शिक्षकों के साथ मारपीट की थी। कुछ वर्ष पहले गंगथ के सरकारी स्कूल के एक छात्र ने सुबह—सवेरे स्कूल ग्राउंड में प्रधानाचार्य का गला पकड़ लिया था। उनकी गलती यह थी कि उन्होंने उस छात्र को एक विद्यार्थी की तरह अनुशासित होने की हिदायत दी थी। अध्यापकों से थप्पड़बाजी, गाली—गलौज, बदसलूकी जैसी घटनाएं तो अब आम होती जा रही हैं। जिस देश का इतिहास गुरु—शिष्य की आदर्श परंपरा के उदाहरणों से भरा पड़ा है, उस देश में आज गुरु—शिष्य के बीच बढ़ती खाई एक समस्या बनती जा रही है। विद्यालय में मुल्क के भविष्य को सींचा जाता है और भाग्य की रेखाएं खींची जाती हैं। इस मुकद्दस जगह पर इल्म के चिराग जला कर गुरु अपने शिष्य के अज्ञान के अंधेरे को दूर करने का प्रयास करता है और उसे अनुशासन, संस्कार और शिष्टाचार का सबक पढ़ाता है। परंतु जो कुछ घटित हो रहा है, उससे साफ जाहिर है कि धीरे—धीरे शिक्षण संस्थान अनुशासनहीनता, बदजुबानी, मारपीट और हिंसा का केंद्र बनते जा रहे हैं।

आज गुरु—शिष्य के संबंधों में वो आत्मीयता नहीं रही। मैं यह तो कतई नहीं कह रहा कि अध्यापक को अपने शिष्य को पीटने का मालिकाना हक है, परंतु अपने शिष्य को सही राह दिखाना, पथभ्रष्ट होने से रोकना, गलती पर टोकना, उसे अनुशासित रहने का सबक सिखाना गुरु के लिए अगर गुनाह हो गया है तो आखिर इन शिक्षा के मंदिरों का औचित्य क्या है? यदि शिक्षण संस्थानों में ऐसा होता रहा तो ऐसे गैरमाकूल वातावरण में गुरु कैसे अपने कर्त्तव्य का निर्वाह कर पाएगा? क्या संत कबीर जी की ये पंक्तिया सिर्फ किताबी छलावा हैं : 'गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढिढ—गढिढ काढ़ै खोट। अंतर हाथ सहार दै, बाहर बाहै चोट।' गुरु और शिष्य के बीच की तनातनी का एक कारण यह है कि दोनों कक्षा में एक—दूसरे से मिलते तो हैं, परंतु उनमें संवाद नहीं होता। गुरु की बात शिष्य नहीं समझ पाता और गुरु शिष्य तक नहीं पहुंच पाता। पढ़ाई किताबों से नहीं, बल्कि दिल से होती है। यदि अध्यापक शिष्य को नहीं समझ पा रहा है तो बेहतर है अध्यापक शिष्य को समझे। अध्यापक और शिष्य का रिश्ता वर्चस्व स्थापित करने का नहीं, बल्कि आपसी समझ का दिलोदिमागी रिश्ता है। गुरु—शिष्य के बीच बढ़ती दूरियों के लिए अभिभावक भी जिम्मेदार हैं। अभिभावक समझते हैं कि शिक्षक महज एक कर्मचारी है जिसे सरकार मोटी तनख्वाह दे रही है या वे मोटी रकम फीस के रूप में अदा कर रहे हैं। वे भूल गए हैं कि गुरु—शिष्य का रिश्ता ग्राहक और दुकानदार का पेशा नहीं है। शिक्षण ऐसा कार्य है जिसमें शिष्य में ज्ञान प्राप्ति का जुनून व समर्पण की भावना होनी चाहिए और गुरु में अपने ध्येय के प्रति निष्ठा। बच्चों के मन में शिक्षक के प्रति आदर भाव भरने की बात तो दूर, अभिभावक उनकी शिकायत करने या उनके विरुद्ध मुकद्दमा दायर करने के लिए आतुर रहते हैं।

ऐसी स्थिति में बच्चों में गुरु के लिए सम्मान की भावना कैसे विकसित होगी? हालांकि विद्यालयों में एसएमसी गुरु—शिष्य—अभिभावक के रिश्तों को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभा सकती है, परंतु ज्यादातर एसएमसी के सदस्य या तो निष्क्रिय हैं या फिर शैक्षणिक कार्यों को पीछे रख कर राजनीति में ज्यादा रुचि लेते हैं। घर बच्चे की पहली पाठशाला होती है और मां—बाप पहले अध्यापक। बच्चों के मानस पटल पर घर के माहौल और वहां मिल रही तरबीयत का गहरा असर होता है। जिस अत्यधिक खुले वातावरण में आज बच्चे पल रहे हैं, उसने उनका भला कम और नुक्सान ज्यादा किया है। अति सर्वत्र वर्जयेत अर्थात किसी भी चीज का आवश्यकता से अधिक होना नुकसानदेह होता है। कुछ माता—पिता 'बैस्ट पापा' या 'बैस्ट मॉम' कहलाने के चक्कर में अपने बच्चों की हर बात या मांग पर 'यैस' कहने की होड़ में शामिल रहते हैं। इस होड़ में न माता—पिता, न ही बच्चे ये समझ पाते हैं कि 'नो' शब्द की अहमियत कितनी है। 'यैस' को सुनते—सुनते बच्चे को 'नो' सुनना अखरने लगता है। अनुशासन में बंधना उसे बोझ लगने लगता है और पता भी नहीं चलता कि बच्चा कब हाथ से निकल गया और राह से भटक गया। वास्तव में यदि उचित समय पर बच्चों को सही राह न दिखाई जाए तो आगे चल कर वे समस्या बन जाते हैं। मां—बाप को याद रखना चाहिए कि यदि उठते जख्म को वक्त पर दवा न मिले तो वह नासूर बन जाता है। बच्चे की बेहतर परवरिश के लिए डांट व दुलार, फटकार व तारीफ, थपेड़े व पुचकार की जरूरत होती है, ताकि उसका विकास एकतरफा न हो। यदि गुरु—शिष्य—अभिभावक विद्यालयों में दोस्ताना तालिमी माहौल नहीं बना सकते तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा 'अगले जन्म मोहे गुरु न बनइयो, ओ राम जी।'

महिला सशक्तिकरण

—प्रो(डॉ)शरद नारायण खरे—

आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। हमारे आदि दृ ग्रंथों में नारी के महत्त्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि ष्यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते है।

लेकिन विडम्बना तो देखिए नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति और दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है, इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा कर सकती हैं राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्त्व और अधिकार के बारे में समाज में जागरुकता लाने के लिये मातृ दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कई सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को कई क्षेत्र में विकास की जरुरत है।

भारत में, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरुरी है, जैसे दृ दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, वैश्यावशति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय।

अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है। जहाँ महिलाएँ अपने परिवार के साथ ही बाहरी समाज के भी बुरे बर्ताव से पीड़ित है। भारत में अनपढ़ो की संख्या में महिलाएँ सबसे अव्वल है।

नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ में आयेगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी ।

स्त्री को सश्जन की शक्ति माना जाता है अर्थात स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। इस सश्जन की शक्ति को विकसित—परिष्कृति कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता का सु—अवसर प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण का आशय है।

दूसरे शब्दों में दृ महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी के मौके मिल सके, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। यह वह तरीका है, जिसके द्वारा महिलाएँ भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकंक्षाओं को पूरा कर सके।

आसान शब्दों में महिला सशक्तिकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाओं में उस शक्ति का प्रवाह होता है, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल के अपेक्षा मध्य काल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आयी। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्य काल में वह सम्मान घटने लगा था।

आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएँ कई सारे महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं, फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएँ आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य है और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध नही है।शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा काफी पीछे हैं। भारत में पुरुषों की शिक्षा दर 81.3 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं की शिक्षा दर मात्र 60.6 प्रतिशत ही है। भारत के शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के अपेक्षा अधिक रोजगारशील है, आकड़ो के अनुसार भारत के शहरों में साफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएँ कार्य करती है, वही ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90 फीसदी महिलाएँ मुख्यतः कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करती है।भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का एक और मुख्य कारण भुगतान में असमानता भी है। एक अध्ययन में सामने आया है कि समान अनुभव और योग्यता के बावजूद भी भारत में महिलाओं को पुरुषों के अपेक्षा 20 प्रतिशत कम भुगतान दिया जाता है।

हमारा देश काफी तेजी और उत्साह के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसे हम तभी बरकरार रख सकते है, जब हम लैंगिग असमानता को दूर कर पाए और महिलाओं के लिए भी पुरुषों के तरह समान शिक्षा, तरक्की और भुगतान सुनिश्चित कर सके। भारत की लगभग 50 प्रतिशत आबादी केवल महिलाओं की है मतलब, पूरे देश के विकास के लिए इस आधी आबादी की जरुरत है जो कि अभी भी सशक्त नहीं है और कई सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी हुई है। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि भविष्य में बिना हमारी आधी आबादी को मजबूत किए हमारा देश विकसित हो पायेगा। महिला सशक्तिकरण की जरुरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्राचीन समय से भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुषप्रधान समाज था। महिलाओं को उनके अपने परिवार और समाज द्वार कई कारणों से दबाया गया तथा उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई और परिवार और समाज में भेदभाव भी किया गया ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दिखाई पड़ता है।

भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिये माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रुप में महिला देवियों को पूजने की परंपरा है लेकिन आज केवल यह एक ढोंग मात्र रह गया ।पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले लैंगिक असमानता और बुरी प्रथाओं को हटाने के लिये सरकार द्वारा कई सारे संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए और लागू किए गए हैं। हालाँकि ऐसे बड़े विषय को सुलझाने के लिये महिलाओं सहित सभी का लगातार सहयोग की जरुरत है।

आधुनिक समाज महिलाओं के अधिकार को लेकर ज्यादा जागरुक है जिसका सुपरिणाम सामने आ रहे हैं।

धान क्रय केंद्र पर तौल न होने से किसान परेशान

किसानों ने जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर तौल शुरू कराने की मांग की

अवध की आवाज ब्यूरो

कहोबा चौराहा गोंडा। धान क्रय केंद्र पर तौल न होने से किसान परेशान। बताते चलें पंडरी कृपाल ब्लाक अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा पंडरी बल्लभ में किसानों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा साधन सहकारी समिति धान क्रय केंद्र बनाया गया है लेकिन किसानों की सहकारी सीमित धान क्रय केंद्र पर धान तौल न होने से किसान काफी परेशान हैं। पंडरी कृपाल ब्लाक अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा पंडरी बल्लभ निवासी पवन कुमार, राम बहादुर, मोहनलाल, मजीत, पंकज कुमार वर्मा, राकेश कुमार सोनकर सहित अन्य लोगों ने बताया कि ग्रामसभा पंडरी वल्लभ में साधन सहकारी समिति पंडरी बल्लभ नामित है और यहां पर साधन सहकारी समिति पर धान क्रय केंद्र चल रहा है लेकिन केंद्र प्रभारी किसानों का धान तौल कराने से इंकार कर रहे हैं। केंद्र प्रभारी द्वारा बताया जा रहा है कि सहकारी सीमित पंड़री बल्लभ में धान क्रय केंद्र पर धान डंप है गोदाम खाली नहीं है गोदाम भरा हुआ है। किसानों का कहना है कि साधन सहकारी समिति पर टीन सेट का एक अतिरिक्त गोदाम भी है। लेकिन केंद्र प्रभारी द्वारा धान तौल कराने से इनकार किया जा रहा है। किसानों ने बताया कि जब नोडल अधिकारी से बात किया गया नोडल अधिकारी साफ इंकार कर रहे हैं किसानों ने इसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही गोंडा को दिया है और सहकारी समिति पर धान तौल कराने की मांग की है।

मोतीगंज थाने के दो उपनिरीक्षक का हुआ स्थानांतरण ,किया गया विदाई समारोह का आयोजन

अवध की आवाज ब्यूरो

कहोबा चौराहा गोंडा। मोतीगंज थाने पर तैनात दो उप निरीक्षकों का तबादला गैर थानों के लिए हो गया था जिनका मंगलवार को विदाई समारोह पर माला पहनाकर मोतीगंज थाने से विदा किया गया आपको बताते चलें कि मोतीगंज थाने पर तैनात उपनिरीक्षक सुनील कुमार यादव का स्थानांतरण परसपुर थाना 15 दिन पहले हुआ था इसी दिन मोतीगंज थाने के उपनिरीक्षक शरद कुमार अवस्थी का स्थानांतरण वजीरगंज थाने पर हुआ था या हस्तांतरण पुलिस अधीक्षक गोंडा के आदेश पर किया गया था जिनका मंगलवार को विदाई समारोह का

कार्यक्रम कर उन्हें माला पहनाकर विदा किया गया आपको बताते चलें कि उप निरीक्षक सुनील कुमार यादव लगभग 3 वर्षों से मोतीगंज थाने में तैनात थे और ज्यादातर मामला यह दोनों पक्षों को बैठा कर सुलह समझौता से ही निपटा देते थे इसलिए मोतीगंज थाना क्षेत्र में इन की काफी सराहना की जाती थी और लोग खुश भी रहते थे पीड़ित को मौके पर न्याय भी मिल जाता था जिसकी वजह से क्षेत्र के लोग उप निरीक्षक सुनील कुमार यादव से काफी खुश दिखे विदाई समारोह में क्षेत्र के लोग भी मौजूद रहे इस समारोह में मोतीगंज थाने के समस्त महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी मौजूद रहे कुछ क्षेत्र के लोगों को इन दोनों उप निरीक्षकों का यहां से जाना काफी दुख हुआ और विदाई के समय आंखों में आंसू आ गए।

जिले में 22 दिसंबर से मनाया जाएगा बाल स्वास्थ्य पोषण माह

नौ माह से पाँच साल तक के बच्चों को दी जाएगी विटामिन ए की खुराक

अवध की आवाज ब्यूरो

रायबरेली। बाल स्वास्थ्य पोषण माह (बीएसपीएम) का आयोजन हर साल जून और दिसम्बर में किया जाता है। इस बार बाल स्वास्थ्य पोषण माह 22 दिसम्बर से 21 जनवरी तक मनाया जाएगा। इस दौरान नौ माह से पांच वर्ष तक के बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन – ए की खुराक जरूर दी जाएगी, क्योंकि यह उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वीएचएनडी) और शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस के माध्यम से विटामिन – ए की खुराक बच्चों को एक सुनिश्चित योजना के अनुसार दी जायेगी। इसकी तैयारियों को लेकर सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में अंतर्विभागीय बैठक हुई।

जिला प्रतिरक्षण अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. रिजवान ने बताया– इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग (आईसीडीएस) एवं स्वयंसेवी संस्थाएं सहयोग करेंगी द्य इस बार करीब 3.31 लाख बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य है, जिसमें नौ माह से 12 माह के 19,314 बच्चे, एक से दो साल के 83,222 बच्चे तथा दो से पाँच साल के 2,28,782 बच्चे हैं। सभी गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए की जाएंगी।

नोडल अधिकारी ने बताया – विटामिन "ए" वसा में घुलनशील है। कोरोना से बचाव में रोग प्रतिरोधक क्षमता महत्वपूर्ण है। नौ माह से पांच वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की नौ खुराक दिये जाने का प्रावधान है। 9 से 12 माह के बच्चों को एक मिली (एक लाख अंतर्राष्ट्रीय यूनिट) मीजल्स एवं रूबेला के पहले टीकाकरण के दौरान, 16 से 24 माह के बच्चों को 2 मिली (दो लाख अंतर्राष्ट्रीय यूनिट) मीजल्स एवं रूबेला के दूसरे टीके के साथ नियमित टीकाकरण सत्र के दौरान, 2 साल से 5 साल के बच्चों को 2 मिली (दो लाख अंतर्राष्ट्रीय यूनिट) 6–6 माह के अन्तराल पर बाल स्वास्थ्य पोषण माह के दौरान दी जाती है।

जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी डा. डी.एस.अस्थाना ने बताया – विटामिन ए की कमी से बच्चों में अंधापन हो जाता है जिसे रोका जा सकता है। विटामिन ए की कमी से गंभीर रोग तथा मृत्यु भी हो सकती है। गर्भवती में विटामिन ए की कमी से रतौंधी (नाईट ब्लाइंडनेस) हो जाता है जो कि मातृ मृत्यु के खतरे को बढ़ाता है।

इस मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अंशुमान सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी संजय सिंह, संध्या श्रीवास्तव, जिला महिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डा. नवीन कुमार, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संजीव गुप्ता, नंदलाल , वंदना त्रिपाठी, यूनिसेफ़ से अनीता एवं सहाना जमीर तथा न्यूट्रीशन इंटरनेशनल से आलोक पांडे और सभी ब्लॉक के ब्लॉक समुदाय प्रक्रिया प्रबंधक (बीसीपीएम) उपस्थित थे।

गुलौली दंगल में बुंदेलखंडी पहलवानों ने दिल्ली को किया परास्त

महिला पुरुष पहलवानों ने दिखाए दांव पेंच भीड़ ने किया उत्साह वर्धन

अवध की आवाज ब्यूरो

कदौरा/जालौन। गुलौली में प्रति वर्ष की भांति आयोजित विशाल दंगल आयोजन में आये महिला पुरुष पहलवानों ने अपने दांव पेंच दिखाये गए जिसमे अधिकांश बुन्देल खण्डी पहलवानों द्वारा दिल्ली व अन्य जगहों से आये पहलवानों को मात देकर जीत हासिल की वही आगंतुक पदाधिकारियों द्वारा पुरुस्कृत कर पहलवानों का उत्साह वर्धन किया। ज्ञातव्य हो कि विकास खण्ड कदौरा क्षेत्र ग्राम गुलौली में गत वर्षो की भांति विशाल दंगल का आयोजन किया गया इस दंगल का शुभारंभ हाजी अनीश खान व सपा नेता हाजी अज़हर वेग व विनोद चतुर्वेदी द्वारा फीता काटकर दंगल का शुभारंभ किया इस अवसर पर दंगल में मौजूद पदाधिकारियों द्वारा कहा की दंगल के आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तम स्वास्थ्य बनाने की प्रतिस्पर्धा बनी रहती है तथा दूर दराज से आए पहलवानों का आपस में कुश्ती के माध्यम से परिचय होता है यह भारतीय संस्कृत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हम सब को सम्मान एवं बढ़ावा देना चाहिए इस अवसर पर ग्राम गुलौली के भूतपूर्व प्रधान हातिम बेग एवं वर्तमान प्रधान नूर बैग पोला बेग तथा दंगल कमेटी के अध्यक्ष यादव जी ने विनोद चतुर्वेदी व पं० नरेन्द्र कुमार तिवारी अध्यक्ष हाथ कागज उद्योग का माल्यार्पण करके स्वागत किया। ग्राम गुलौली के इस दंगल में हरियाणा पंजाब फर्रुखाबाद उन्नाव कानपुर झांसी हमीरपुर के अलावा जनपद जालौन के भी नामी–गिरामी पहलवानों ने भाग लिया जिसमें प्रमुख रुप से चांद उन्नाव मुकेश कानपुर छोटू कानपुर धर्मेंद्र फर्रुखाबाद दीपू जालौन अंकित झांसी के बीच शानदार कुर्तियां हुई। ग्राम गुलौली में यह दंगल सुर्य मंदिर की यादगार में पिछले 50 वर्षो से लगातार होता चला आ रहा है यह दंगल बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक बना हुआ है दंगल आयोजन समिति के संयोजक भूतपूर्व प्रधान हातिम

बैग तथा पोला वेग के कुशल संचालन में यह दंगल हो रहा है इस दंगल में नरेन्द्र कुमार तिवारी वरिष्ठ पत्रकार, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी अजहर वेग पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि, अनीस ठेकेदार, जुनैद पहलवान अमरौदा, प्रदीप दीक्षित ग्राम प्रधान कीरतपुर पवन दीप निषाद पत्रकार, ग्राम प्रधान देवकली बालसिंह निषाद, पूर्व प्रधान परमानंद कुशवाहा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर पहलवानों का उत्साहवर्धन किया।

एसपी ने की अपराध समीक्षा,कोतवाली का किया निरीक्षण

अवध की आवाज ब्यूरो

उरई, जालौन। एसपी रवि कुमार ने देर रात कोतवाली में अपराध समीक्षा के दौरान जहां अभिलेखों की जांच की वहीं कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश अधीनस्थों

को दिए। सर्दी में उन्होंने पिकेट और गश्त बढ़ाने पर भी जोर दिया एसपी रवि कुमार शनिवार की रात कोतवाली पहुंचे जहां उन्होंने कोतवाली परिसर का निरीक्षण किया और जहां जहां कमियां दिखाई दीं उन्हें जल्द दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही अभिलेखों की भी जांच की तथा उपनिरीक्षकों के साथ बैठक करके लंबित विवेचनाओं को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए उन्होंने इलाके में गश्त निरंतर किए जाने और जरूरी स्थानों पर पिकेट लगाए जाने के कड़े निर्देश दिए। चौकी इंचार्ज और बीट इंचार्जों के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी पीड़ित कोतवाली आए उसे तुरंत न्याय मिले, महिलाओं की सुरक्षा पर भी उन्होंने अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश दिए। चुनाव के मद्देनजर अपराधियों और अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखने तथा वांछित और वारंटियों की गिरफ्तारी के भी उन्होंने निर्देश दिए। इस दौरान कई उपनिरीक्षक मौजूद रहे।

गलन बढ़ी, न्यूनतम पारे का गिरना जारी, पर क्रिसमस पर राहत के आसार, दिन का पारा 20 डिग्री और न्यूनतम पारा 5.5 डिग्री रिकॉर्ड

लखनऊ। लखनऊ राजधानी में न्यूनतम पारे के गिरने के साथ ही गलन का बढ़ना जारी है। हालांकि मौसम विभाग क्रिसमस पर ठंड–गलन से थोड़ी सी राहत

मिलने के आसार जता रहा है। राजधानी में सुबह हलके कोहरे के साथ हुई। दोपहर बात हलकी धूप तो खिली, लेकिन पछुआ हवाओं केजोर के आगे उनकी एक न चली। सूरज लालिमा लिए आसमान में ठंड से ठिठुरता सा रहा। मौसम बुलेटिन में दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम रहा। जबकि न्यूनतम पारा बीते रविवार के 6.7 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले 5.5 डिग्री दर्ज हुआ। यह सामान्य से 3.2 डिग्री कम रहा। वहीं हवाओं की रफ्तार 10 किमी प्रति घंटा रही, लेकिन पछुआ हवाएं इतनी तेज थी कि वह सुई की तरह चुभ रही थीं। मौसम विभाग के विशेषज्ञों व वेबसाइट पर जारी अनुमान के मुताबिक, 24 दिसंबर तक कोहरा रहने, गलन महसूस होने के आसार हैं। 25–26 को इससे राहत मिल सकती है। जबकि इसके बाद फिर सर्दी तेजी पकड़ेगी। जो संकेत मिल रहे हैं, उसके मुताबिक नए साल का स्वागत हाड़ कंपाने वाली भीषण ठंड कर सकती है।

धान खरीद में गड़बड़ी करने वाले क्रय प्रभारियों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, डीएम ने दिए आदेश

अवध की आवाज ब्यूरो

गोंडा। आप लोगों को बताते चलें कि डीएम गोंडा मारकंडे शाही ने बताया कि धान की खरीदारी में दलाली करने व किसान को किसी प्रकार की परेशानी होने पर जानकारी मिलने पर किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा इस तरह से उन्होंने कहा कि धान की खरीदारी में दलाली करने वाले को किसी तरह से क्षमा नहीं किया जाएगा क्योंकि किसान अन्नदाता है उसकी गाढ़ी कमाई को इस तरह से बिचौलियों के द्वारा दलालों के द्वारा घटतौली करके उन्हें परेशान न किया जाए।

जिलाधिकारी ने सभी क्रय एजेंसियों को लिखित रूप से पत्र जारी कर सख्त निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में विभिन्न कय एजेंसीज के संचालित धान कय केन्द्रों पर अपने उत्पाद के विपणन हेतु आने वाले किसानों द्वारा प्रायः यह शिकायत की जाती है कि उन्हें करें केन्द्रों पर काफी समय तक इंतजार कराया जाता है अथवा कोई न कोई कमी बताकर धान खरीद करने से मना किया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि जनपद में कुल 98 धान कय केन्द्र स्थापित व संचालित हैं,। इनमें खाद्य विपणन विभाग के 13, पीसीएफ के 24 यूपीएसएस के 22, यूपीपीसीयू के 35 तथा भारतीय खाद्य निगम व मण्डी समिति के 2–2 कय केन्द्र हैं। उन्होने जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देशित किया है। कि निरन्तर इस बात पर बल दिया जा रहा है कि कय केन्द्रों पर किसानों को

अपने उत्पाद के विपणन में सहयोग प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी किसान को परेशान न होना पड़े, इसके बावजूद किसानों की ओर से प्राप्त होने वाली शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई हैं। अतः लापरवाह व किसानों का धान खरीदने में आनाकानी करने वाली क्रय एजेंसी के जिला प्रभारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जाय। उन्होंने निर्देशित किया है कि धान क्रय केन्द्रों पर आने वाले किसानों को सुगमतापूर्वक अपने उत्पाद का विपणन सुनिश्चित कराने तथा वहा की व्यवस्थाओं के पर्यवेक्षण हेतु यह आवश्यक है कि क्रय एजेंसीज के जिला प्रभारी प्रतिदिन अधिक से अधिक कय केन्द्रों का निरीक्षण करें और वहां पर व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण करते हुए किसानों से फीडबैक भी प्राप्त करें और यदि किसी कय केन्द्र प्रभारी द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही की जा रही है । अथवा किसानों का शोषण करने की पुष्टि होती है तो सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के साथ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, जिला प्रबन्धक पीसीएफ, जिला प्रभारी यूपीएसएस तथा जिला प्रभारी यूपीपीसीयू अपने विभाग व एजेंसी के कम से कम पांच–पांच क्रय केन्द्रों का प्रतिदिन निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप पर प्रतिदिन उन्हें उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सचिव मण्डी समिति गोण्डा एवं मण्डी समिति नवाबगंज अपने कय केन्द्रों का प्रतिदिन निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसी प्रकार क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनी एजेंसी के दोनों कय केन्द्रों का प्रतिदिन निरीक्षण करते हुए कार्यवाही संपादित की जाएगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा विपणन शाखा के कय केन्द्रों के साथ–साथ अन्य एजेंसीज के क्रय केन्द्रों का भी रैण्डम तौर पर निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का गहनता के साथ पर्यवेक्षण किया जाएगा। तथा पाई गई कमियों का निराकरण कराते हुए निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की जाएगी। क्रय एजेंसी के जिला प्रभारियों को आगाह किया है कि समस्त क्रय केन्द्रों का संचालन शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप सुनिश्चित कराते हुए यह भी देखें कि कृषकों को अपने उत्पाद का विपणन करने के 72 घंटे के अन्दर भुगतान अवश्य प्राप्त हो जाए।

करोड़ों रुपए खर्च...फिर भी गोशाला में भूख और बीमारी से मर रहीं गायें

माधौगढ़, जालौन। सूबे में भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिखाया गया गाय प्रेम और गोवंशीय पशुओं को बचाने की मुहिम को आम जनता भी जानती है। मगर, अफसर इन सबको धता–बताकर पूरे सिस्टम को पलीता लगाने में लगे हैं गायों की देखभाल के नाम पर करोड़ों का बजट खर्च हो गया। मगर, गोशाला की गायें फिर भी जीवित नहीं बच पा रही हैं गोशाला में गायें भूख और बीमारी से लगातार मर रही हैं। उनके शव कई दिनों से गोशाला के अंदर और बाहर कीचड़ में पड़े होकर सड़ रहे हैं। मगर, गोशाला की जिम्मेदारी संभालने का दावा करने वाले सीवीओ को इन सबकी खबर ही नहीं थी। इतना ही नहीं, जनपद जालौन की माधौगढ़ तहसील क्षेत्र के सिहारी गांव की गोशाला में जो गायें जिंदा भी बची हैं, वह इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि चलने लायक नहीं हैं। और साथ ही गायों के शव गौशाला में ही पडे हुए हैं इससे गोशाला की बदहाल व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है किसी ने समाचार दफ्तर में फोन करके बताया कि जालौन के सिहारी गांव में बनी गोशाला के बाहर की जमीन पर कुछ गायों के शव और हड्डियां पड़े हैं। इसके बाद पत्रकारों टीम ने सिहारी गांव की गौशाला में जाकर मौके पर देखा तो बात वाकई सच निकली। गोशाला में पशुओं को खाने के लिए भरपूर चारा मिलना तो दूर की बात है, भरपेट पानी भी नहीं मिल रहा। गोशाला परिसर में गोबर और गंदगी फैली हुई थी। पशुओं के बैठने का साफ स्थान नहीं था। गायों को जो चारा या भूसा खिलाया जाता है, सामने दिखने पर लगा कि वह चारा भी कर्मचारी गोबर में ही डाल देते हैं। गायें गोबर या गंदगी से सना वह चारा खाती नहीं। पीने के लिए जो पानी दिया जाता है, उसमें कीड़े पड़े थे। हालत यह कि गायें न तो ठीक से चारा खा पाती हैं, न ही सर्दी में भर पेट पानी पी सकती हैं। इसलिए गोशाला में कुछ गायें भूख से मर रही हैं तो कुछ बीमारी से। फिलहाल, गोशाला के अंदर गायों के मरने का सिलसिला लंबे समय

से जारी है। खास बात यह है कि मरने के बाद गायों के शव वहीं कीचड़ में ही पड़े सड़ रहे हैं। न तो उनका पोस्टमार्टम कराया गया, न ही उन्हें दफन करने की सुध ली गई। पशुओं के शव गोशाला में जहां–जहां पड़े हुए थे। ये कई दिन पुराने प्रतीत हो रहे थे। हालांकि, गोशाला में रहने वाले कर्मचारी पहले तो मृत पशुओं को जिंदा बताते रहे। काफी हील हुज्जत के बाद बीती रात गायों के मरने की बात कहकर परदा डालने की कोशिश की। कुछ कर्मचारियों ने तो यहां तक कह दिया कि गायें भूख और इलाज के अभाव में नहीं, बैठने की जगह न होने के कारण मर गईं। फिलहाल, लापरवाही का यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में गोशाला के अंदर जिंदा बची गायें भी बहुत दिन तक बची नहीं रहेंगी।

भाजपा सरकार आने पर जगी थी लोगो की उम्मीदें

साल 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। उसमें भी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय गोशाला में सुधार की उम्मीद हर किसी को जाग उठी। बीते साल सरकार की ओर से गोवंश संरक्षण मुहिम शासन स्तर से शुरू भी की गई। इसमें सड़कों पर घूमने वाले गोवंशीय पशुओं को छत, खानपान और इलाज की व्यवस्था कराने के लिए गोशालाओं में ले जाने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए। इसके बावजूद अधिकांश गोशालाओं का हाल बद से बदतर है। मगर, उनमें जनपद जालौन की माधौगढ़ तहसील क्षेत्र के सिहारी गांव की गोशाला का दृश्य अगर कोई देख ले तो उसके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे।

ग्राम पंचायत खिरई खिरवा के मजरा पिपरा सूरमणि में धड़ल्ले से फल फूल रहा है अवैध रूप से कच्ची देसी शराब, का धंधा

अवध की आवाज ब्यूरो

गोंडा। थाना मोतीगंज से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ग्रामसभा पड़ता है खिराई खिरवा के मजरा पिपरा सूर्यमणि में दिनदहाड़े अर्थात शाम ढलते ही अवैध रूप से दारू की होती है बिक्री गांव अर्थात कई गांव के लोग शाम से ही मजरा पिपरा सूर्यमणि में घुस जाते हैं और दारु पीने के पश्चात आपस में गाली गलौज करते हुए अपने अपने रास्ते बढ़ बढ़ाते हुए लड़ते हुए निकल जाते हैं यह प्रक्रिया शाम लगभग 5:30 बजे के बाद से प्रारंभ होती है इस तरह से जबकि एसपी गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया था कि अपने–अपने क्षेत्रों में कहीं भी अवैध रूप से कच्ची शराब का जो कि एक जहर के रूप में समाज में फैल रहा है इसे तत्काल रुप से बंद होना चाहिए । ऐसे अराजक तत्वों को अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखाना चाहिए क्योंकि यह वह नशीला जहर है जो समाज में बुजुर्गों के अलावा 9 युवकों पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। वह नवयुवक जो कल के भारत के भाग्य विधाता बन सकते हैं उनका इस तरह समाज में रहते हुए गंदी आदतों का शिकार हो सकते हैं, ।हो रहे हैं । विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि ग्राम पंचायत ीपतंप खिरवा के पिपरा सूर्यमणि गांव में सूर्य ढलते ही पास पड़ोस गांव के कई लोग शाम को लगभग 5:30 बजे के बाद गाली गलौज करते हुए मजरा पिपरा सूर्यमणि मैं प्रवेश करते हैं । इस प्रकार से कई स्थानों पर शराब भट्टी में देसी अवैध शराब महिला व पुरुष बनाकर के लोगों को बेचते हैं इस तरह से थाना मोतीगंज पुलिस को जो कि शासन का निर्देश भी प्राप्त है उन्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए जिससे समाज में लोगों पर इसका बुरा प्रभाव ना पढ़ सके।

आप लोगों को बताते चलें कि थाना मोतीगंज क्षेत्र में 1 ग्राम सभा पड़ता है सीहा गांव सिया गांव में भी धड़ल्ले से दिनदहाड़े और शाम डलते ही दारु पीने वालों की कतार लग जाती है यह लोग देसी कच्ची अवैध शराब को लोगों में बेच रहे हैं दारु पीने वाले दारु पीने के पश्चात गाली गलौज करते हुए बाहर निकलते हैं जिसका समाज में बुरा असर पड़ता है नवयुवक लोग इन्हीं लोगों का अनुसरण करते हुए दारु पीने का आदी हो रहे हैं ऐसी बात नहीं है पुलिस प्रशासन इस बात को जानती है अर्थात थाना

मोतीगंज के पुलिस विभाग जानते हैं खुद भी कि किस–किस ग्राम सभा में कहां–कहां दारू बनता व बिकता है फिर भी यह लोग नजरअंदाज करते हुए उस पर अपने कर्मो का उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं जिससे समाज में यह बहुत ही बुरा कैंसर का रूप ले सकता है। यदि पुलिस सख्त रवैया अपनाएं निश्चित है कि जोकि थाना क्षेत्र के कई ग्राम सभाओं में देसी शराब अवैध रूप से बन रही है उस पर लगाम लगाया जा सकता है।

धान खरीद में गड़बड़ी करने वाले क्रय प्रभारियों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, डीएम ने दिए आदेश

अवध की आवाज ब्यूरो

गोंडा। आप लोगों को बताते चलें कि डीएम गोंडा मारकंडे शाही ने बताया कि धान की खरीदारी में दलाली करने व किसान को किसी प्रकार की परेशानी होने पर जानकारी मिलने पर किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा इस तरह से उन्होंने कहा कि धान की खरीदारी में दलाली करने वाले को किसी तरह से क्षमा नहीं किया जाएगा क्योंकि किसान अन्नदाता है उसकी गाढ़ी कमाई को इस तरह से बिचौलियों के द्वारा दलालों के द्वारा घटतौली करके उन्हें परेशान न किया जाए।

जिलाधिकारी ने सभी क्रय एजेंसियों को लिखित रूप से पत्र जारी कर सख्त निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में विभिन्न कय एजेंसीज के संचालित धान कय केन्द्रों पर अपने उत्पाद के विपणन हेतु आने वाले किसानों द्वारा प्रायः यह शिकायत की जाती है कि उन्हें करें केन्द्रों पर काफी समय तक इंतजार कराया जाता है अथवा कोई न कोई कमी बताकर धान खरीद करने से मना किया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि जनपद में कुल 98 धान कय केन्द्र स्थापित व संचालित हैं,। इनमें खाद्य विपणन विभाग के 13, पीसीएफ के 24 यूपीएसएस के 22, यूपीपीसीयू के 35 तथा भारतीय खाद्य निगम व मण्डी समिति के 2—2 कय केन्द्र हैं। उन्होने जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देशित किया है। कि निरन्तर इस बात पर बल दिया जा रहा है कि कय केन्द्रों पर किसानों को अपने उत्पाद के विपणन में सहयोग प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी किसान को परेशान न होना पड़े, इसके बावजूद किसानों की ओर से प्राप्त होने वाली शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई हैं। अतः लापरवाह व किसानों का धान खरीदने में आनाकानी करने वाली क्रय एजेंसी के जिला

प्रभारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जाय। उन्होंने निर्देशित किया है कि धान क्रय केन्द्रों पर आने वाले किसानों को सुगमतापूर्वक अपने उत्पाद का विपणन सुनिश्चित कराने तथा वहा की व्यवस्थाओं के पर्यवेक्षण हेतु यह आवश्यक है कि क्रय एजेंसीज के जिला प्रभारी प्रतिदिन अधिक से अधिक कय केन्द्रों का निरीक्षण करें और वहां पर व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण करते हुए किसानों से फीडबैक भी प्राप्त करें और यदि किसी कय केन्द्र प्रभारी द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही की जा रही है । अथवा किसानों का शोषण करने की पुष्टि होती है तो सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के साथ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, जिला प्रबन्धक पीसीएफ, जिला प्रभारी यूपीएसएस तथा जिला प्रभारी यूपीपीसीयू अपने विभाग व एजेंसी के कम से कम पांच—पांच क्रय केन्द्रों का प्रतिदिन निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप पर प्रतिदिन उन्हें उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सचिव मण्डी समिति गोण्डा एवं मण्डी समिति नवाबगंज अपने कय केन्द्रों का प्रतिदिन निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसी प्रकार क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनी एजेंसी के दोनों कय केन्द्रों का प्रतिदिन निरीक्षण करते हुए कार्यवाही संपादित की जाएगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा विपणन शाखा के कय केन्द्रों के साथ—साथ अन्य एजेंसीज के क्रय केन्द्रों का भी रैण्डम तौर पर निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का गहनता के साथ पर्यवेक्षण किया जाएगा। तथा पाई गई कमियों का निराकरण कराते हुए निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की जाएगी। क्रय एजेंसी के जिला प्रभारियों को आगाह किया है कि समस्त क्रय केन्द्रों का संचालन शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप सुनिश्चित कराते हुए यह भी देखें कि कृषकों को अपने उत्पाद का विपणन करने के 72 घंटे के अन्दर भुगतान अवश्य प्राप्त हो जाए।

पुलिस अधीक्षक ने किया अर्दली रूम का निरीक्षण

बैठक में पत्रकारों का नही किया सम्मान व थाना प्रभारी ने कुछ ही पत्रकारों को दी निरीक्षण की सूचना

अवध की आवाज ब्यूरा

माधौगढ़, जालौन। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने माधौगढ़ तहसील के अर्दली रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ—सफाई का भी जायजा लिया। कोतवाली की टूटी फूटी पड़ी बाउंड्री, बिल्डिंग, शौचालय, आवास रूम, भोजनालय रसोई, बन्दीगृह, कम्प्यूटर कार्यालय कक्ष, आगन्तुक कक्ष, मालखाना दस्तावेज, अस्त्र शस्त्र कराते समय डांट फटकार लगाई खस्ताहाल व्यवस्था को देख पुलिस कप्तान ने ज़िम्मेदारों को फटकार लगाई तथा इन कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए और पुलिस कर्मियों से अस्त्र शस्त्र के बारे में बारीकी से पूछ ताछ की वह देखना चाहते थे कि कहि कोई कमी बेसी तो नही है इसके पश्चात क्षेत्र के सभी प्रधानों, राजनीतिक दलों के नेता, स्वास्थ्य विभाग, आमजनमानस, और पत्रकारों के साथ समीक्षा बैठक की बैठक में लंबित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया इसके साथ बैठक में कुछ ही पत्रकारों का सम्मान किया इससे क्षेत्र के पत्रकारों ने नाराजगी जाहिर की कहा कि पुलिस अधीक्षक ने पहले ही निर्देश दिए थे कि क्षेत्र के समस्त पत्रकारों की मीटिंग बुलाई जाए और सभी से परिचय करे इसके बाद भी थाना प्रभारी अजय कुमार अवस्थी द्वारा पत्रकारों को कोई सूचनाएं नही दी हा कुछ रजे पटे पत्रकारों का ही सम्मान किया गया ताकि वह नदारत करने पर जिम्मेदार पर सवाल भी खड़े हो रहे है कि आखिर ऐसी क्या बजह रही जो चंद पत्रकारों को छोड़ बाकी पत्रकारों को कार्यक्रम से दूर रखा गया इस दौरान क्षेत्राधिकारी राहुल पांडेय समस्त थाना प्रभारी व औरैया सर्किल के समस्त विवेचनाधिकारी मौजूद

जिम्मेदार की भूरी प्रशंशा करसके साथ ही उनकी पत्रकारों ने नाराजगी जताई की पत्रकारों का सम्मान क्यों नही होता जबकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे सगम्भ है। मीडिया कर्मियों को इस तरह रहे और साथ ही वांछित व वारंटी अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए कहा। पुलिस अधीक्षक ने कहाकि जो आदेश निर्देश दिए गए हैं।उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। इसमें लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जनकवि अदम गोंडवी की दसवीं पुण्यतिथि के अवसर पर काव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया

अवध की आवाज ब्यूरो

मनकापुर,गोंडा। जनकवि अदम गोंडवी की 10 वीं पुण्यतिथि के अवसर पर करनैलगंज क्षेत्र के चचरी बाजार में अनुभूति सामाजिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक संस्था के तत्वाधान में कविसम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता संस्था के नेता अवधेश सिंह व संचालन तरबगंज से आये रवीन्द्र पांडेय रवि ने किया। उच्चतर सेवा आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर शेर बहादुर सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्णण करके व दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। परसपुर के ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि अजय सिंह ने कवियों के साथ क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों को अंगवस्त्र व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की प्रतिमा भेंटकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुये केबी.सिंह, पूर्व नपाप अध्यक्ष शमीम अहमद अच्छन व प्रख्यात साहित्यकार डॉ. उमा सिंह, डॉ. एके सिंह, सहित कई अन्य लोगों ने अदम गोण्डवी

के जीवन व उनकी रचनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उसके बाद कवियों ने बारी बारी से अपनी रचनायें प्रस्तुत की। जिसका शुभारम्भ जयदीप सिंह सरस की वाणी वन्दना से हुआ। कवयित्री ज्योतिमा शुक्ला रश्मि ने कहा—वो जो बातें हजार करते हैं, झूठा करार करते हैं। महिला कवयित्री संदीप सुरीला ने कहा—चाहे सुख हो या दुख साथ मिलकर काटिये, नफरतों के दौर में प्यार सब में बांटिये। रवीन्द्र पांडेय ने कहा—नापाक इरादे हैं तेरे और चाल तेरी शैतानी, नेस्तनाबूद हो जायेगा यह है ताकत हिंदुस्तानी है। डॉ. अनिल सिंह बौझड, जयदीप सिंह सरस,ज्योतिमा शुक्ल ओम शर्मा ,रामायण धर द्विवेदी, कृष्ण कुमार सिंह, याकूब अज्म गोंडवी, हरीश शुक्ला, सृजन शुक्ला सहित अन्य कई कवियों ने अपनी रचनायें पढ़ीं। इस दौरान देवेंद्र सिंह अधिवक्ता हाईकोर्ट, अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के राष्ट्रीय सचिव रमेश सिंह, प्रदेश सचिव ठाकुर उग्रसेन सिंह, राजेन्द्र अवस्थी, त्रिलोकीनाथ तिवारी, आशीष गोस्वामी, एके गोस्वामी, गब्बू सिंह, चन्दर सिंह,सुनील सिंह, कक्कन शुक्ला,चन्दर सिंह, विवेक सिंह, जिला पँचायत, अजय सिंह, गुड्डू सिंह जिला पंचायत, पिंकू सिंह, संजय सिंह, गुडडू सिंह मलाव, हितेश सिंह अभय सिंह समेत सैकड़ो की संख्या में लोग मौजूद रहे।

देवबंद के मौलवियों ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का किया विरोध

मुजफ्फरनगर, (वेब वार्ता)। प्रसिद्ध इस्लामिक मदरसा दारुल—उलूम देवबंद के मौलवियों ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के केंद्र के फैसले का विरोध किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खापों ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और घोषणा की है कि वे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक महा पंचायत बुलाएंगे। देवबंद के मौलवियों ने कहा है कि ऐसा लगता है कि फैसला जल्दबाजी में लिया गया है और इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जमीयत दावत उल मुस्लिमीन के संरक्षक इशाक गोरा ने कहा कि अगर केंद्र सरकार इसे कानून बनाना चाहती है, तो उन्हें सभी ध र्मो के धर्मगुरुओं से सलाह लेनी चाहिए थी। मौलवी ने आगे कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां लोग सरकार से ज्यादा धार्मिक प्रमुखों का पालन करते हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार को कोई भी कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के बाद सरकार को इसे लागू करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देवबंद के एक अन्य मौलवी मुफ्ती असद कासमी ने कहा, वे (सरकार) किसी की नहीं सुनते। अगर वे इसे कानून बनाना चाहते हैं, तो वे ऐसा करेंगे। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि अगर एक लड़का और एक लड़की ने सही समय पर शादी नहीं की, तो जोखिम है कि वे पाप कर सकते हैं। इसलिए, उनकी शादी कम उम्र में कर देनी चाहिए। कई खापों ने भी केंद्र के फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध में वश्द्धि होगी। खापों ने कहा कि निर्णय लोगों के निजी जीवन में हस्तक्षेप के बराबर है। बीकेयू नेता और बलियां खाप के प्रमुख नरेश टिकैत ने कहा, माता—पिता को यह तय करने का एकमात्र अधिकार होना चाहिए कि उनकी बेटियों की शादी कब की जाए। थंबा खाप नेता चौधरी बश्जपाल ने कहा, इस कदम से समाज में अपराध बढ़ेगा। लड़कियों की शादी 16 साल की उम्र में कर देनी चाहिए। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला लिया है। पुरुषों के लिए शादी की कानूनी उम्र 21 साल है। इस फैसले के साथ सरकार दोनों की शादी की उम्र को बराबर कर देगी।

डाक विभाग द्वारा भारत सरकार को सम्बोधित पोस्टकार्ड निबन्ध प्रतियोगिता का किया गया आयोजन

अवध की आवाज ब्यूरो

गोंडा। देश भर में मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत भारतीय डाक विभाग द्वारा देश भर में भारत के प्रधान मंत्री को सम्बोधित पोस्ट निबन्ध प्रतियोगिता की शुरुवात की गयी है। इसी के तहत सोमवार को धानेपुर क्षेत्र के बालिका इंटर कालेज में पोस्टकार्ड निबन्ध प्रतियोगिता का संचालन किया गया, जिसमे विद्यालय के बच्चों से अति संक्षिप्त शब्दों में निबन्ध लिखवाया गया सभी निबन्ध पत्रों को संकलित करके पैकेट के रूप में डाक विभाग द्वारा तय शुदा पते पर प्रेषित किया जाएगा जहां उच्च लेखनी वाले छात्रों को चयनित किया जाएगा, निबन्ध में बच्चों को देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण देने वाले उन वीर बलिदानियों का नाम उजागर करना है जिन्हें प्रमुखता नही दी गयी है साथ ही कल्पना भाषित करना है की 2047 में मनाया जाने वाला आजादी महोत्सव कैसा होगा इस पर आधारित निबन्ध छात्राओं द्वारा लिखे गए हैं इस प्रतियोगिता में सैकड़ों छात्राओं ने हिस्सा लिया, इस मौके पर जी.डी. एस. कर्मचारी संघ के वरिष्ट

पदाधिकारी रामानन्द तिवारी सहित विद्यालय का स्टाप उपस्थित रहा।

शादी की उम्र तय करने से परहेज करे सरकार : मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

लखनऊ, (वेब वार्ता)। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करार देते हुए विवाह की आयु तय करने से परहेज करने का आग्रह किया है। बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सोमवार रात जारी एक बयान में कहा कि शादी जीवन की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है लेकिन विवाह की कोई उम्र तय नहीं की जा सकती क्योंकि यह समाज के नैतिक मूल्यों के संरक्षण और नैतिक वंचना से समाज के संरक्षण से जुड़ा मामला भी है। उन्होंने कहा ''यही वजह है कि इस्लाम समेत विभिन्न ध र्मों में शादी के लिए कोई उम्र तय नहीं की गई है। यह पूरी तरह से अभिभावकों के विवेक पर निर्भर करता है। अगर किसी लड़की के अभिभावक यह महसूस करते हैं कि उनकी बेटी 21 साल की उम्र से पहले ही शादी के लायक है और वह शादी के बाद की अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभा सकती है तो उसे शादी से रोकना क्रूरता है और किसी वयस्क की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप भी है। इससे समाज में अपराध बढ़ने की भी आशंका है। बोर्ड महासचिव ने कहा ष्लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किया जाना और निर्धारित उम्र से पहले विवाह करने को अवैध घोषित किया जाना ना तो लड़कियों के हित में है और ना ही समाज के। बल्कि इससे नैतिक मूल्यों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। बोर्ड के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किए गए इस बयान में मौलाना रहमानी ने यह भी कहा कि कम उम्र में लड़कियों की शादी करने का चलन अब धीरे—धीरे गायब हो रहा है लेकिन कभी—कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब लड़की की शादी निर्धारित उम्र से पहले करना उसके हित में होता है लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार से मांग करता है कि वह ऐसे अनुपयोगी और नुकसानदेह कानून बनाने से परहेज करे। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते लड़कियों की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 वर्ष करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

बलिया में नाबालिग दलित किशोरी से बलात्कार के दोषी को उम्रकैद

बलिया, (वेब वार्ता)। बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने 14 वर्षीय एक दलित किशोरी को अगवा कर उसका बलात्कार करने के एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने मंगलवार को बताया कि जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को 27 अक्टूबर, 2020 की रात इसी कोतवाली क्षेत्र के मेरु राय का पुरा गांव निवासी सुगन ने अगवा कर लिया था। सुमन ने किशोरी को अगवा करने के बाद उससे बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में किशोरी के पिता की शिकायत पर रसड़ा कोतवाली में सुगन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अलावा पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम और एससी/एसटी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) कानून की सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। पाठक ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश गोविंद मोहन की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सोमवार को आरोपी सुगन को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

एक्सप्रेस—वे पर चालक को झपकी लगने से पलटी कार, एक की मौत, चार घायल

उन्नाव। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस—वे पर हसनगंज थाना क्षेत्र के मटरिया गांव के पास चालक को झपकी लगने से तेज रफ्तार कार डिवाइडर फांदकर दूसरी लेन में जाकर पलट गई। हादसे में कैंसर पीड़ित मरीज की मौत हो गई। एक महिला सहित चार लोग घायल हो गए। दो को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। कार सवार चंडीगढ़ से कैंसर पीड़ित मरीज को लेकर सुल्तानपुर जा रहे थे। जनपद सुल्तानपुर के लम्बुआ थाना क्षेत्र के गोरेन गांव निवासी श्यामलाल (48) चंडीगढ़ में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। जिसे कुछ दिन पहले कैंसर होने पर इसके ही साथ चंडीगढ़ में रह रहा प्रतापगढ़ जिले के थाना अल्टा के सराय भानी निवासी प्रेम वर्मा (18) और जिला अम्बाला कैंट के थाना भरतनगर में रहने वाले श्यामलाल के बहनोई बलबीर ने श्यामलाल को चंडीगढ़ में ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां हालत में सुधार न होने पर डाक्टरों ने घर ले जाने के लिए बोल दिया। जिस पर श्यामलाल की पत्नी शमला (45) जिला सुल्तानपुर के संग्राम पुर थाना क्षेत्र के कोलूहा थिरांह निवासी रामसिंह (30) के साथ पति श्यामलाल को लेने चंडीगढ़ गई थी। मंगलवार सुबह 7 बजे सभी एक्सप्रेस—वे के रास्ते सुल्तानपुर जा रहे थे। हसनगंज थाना क्षेत्र के मटरिया गांव के पास कार चला रहे राम सिंह को झपकी लगने से तेज रफ्तार कार डिवाइडर फांदकर दूसरी लेन में जाकर एक्सप्रेस—वे पर पलट गई। हादसे में कैंसर पीड़ित श्यामलाल की मौत हो गई और उसकी पत्नी शमला, बहनोई बलवीर, पड़ोसी प्रेम वर्मा और चालक रामसिंह घायल हो गए। यूपीडा की रेस्क्यू टीम ने घायलों को औरास पीएचसी में भर्ती कराया। यहां से चालक राम सिंह और पड़ोसी प्रेमवर्मा को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यूपीडा ने क्षतिग्रस्त कार मटरिया टोल पर खड़ी कराया है। हसनगंज पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

लखीमपुर खीरी मामले और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा, लोस की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा अदालत में दिये आवेदन की पश्ष्ठभूमि में केंद्रीय गश्ह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। इसके कारण सदन की कार्यवाही आरंभ होने के करीब 50 मिनट बाद अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। कई सदस्यों ने हाथों में तख्तियां भी ले रखी थीं। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर—शराबे के बीच ही प्रश्नकाल शुरू कराया। गृह, कृषि, ग्रामीण विकास मंत्रालयों से जुड़े पूरक प्रश्न पूछे गए जिनके संबंधित मंत्रियों ने उत्तर भी दिए। बिरला ने नारेबजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने की अपील की। बिरला ने सदस्यों से कहा कि आप अपने स्थान पर जाएं, पूरा मौका दूंगा। आपको हर मुद्दे पर पूरा समय दूंगा। आप नियोजित तरीके सदन में व्यवध ाान डालते हैं, ये उचित नहीं है। आप अपने सीट पर जाइए। उन्होंने कहा, ''(सत्र के) अंतिम दिन आग्रह कर रहा हूं कि आप प्रयास करें कि सदन चलें। आप सदन की गरिमा बनाए रखें। सदन में हंगामा जारी रहने पर उन्होंने दिन में 11 बजकर करीब 50 मिनट पर कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले पर ही सोमवार तथा गत सप्ताह बुधवार, बश्हस्पतिवार और शुक्रवार को भी विपक्षी सदस्यों ने सदन में हंगामा किया था जिसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई थी।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभी सांसदों को संगठन के साथ बेहतर तालमेल बनाने की नसीहत

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी पार्टी सांसदों को संगठन के साथ बेहतर तालमेल बनाने की नसीहत देते हुए कहा है कि सांसदों को अपने—अपने जिलों के जिलाध्यक्ष और सभी मंडल अध्यक्षों के साथ लगातार संपर्क में रहना चाहिए और साथ ही निरंतर संवाद भी बनाए रखना चाहिए। उन्होंने सांसदों को सशक्त बूथ और पन्ना प्रमुख स्तर पर भी जुड़ने और कमियों को दूर करने की नसीहत दी। दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में मंगलवार को हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने सभी सांसदों को संसद के आगामी (बजट सत्र) सत्र से पहले सांसद खेल स्पर्धा को पूर्ण कर लेने को भी कहा। नड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन , 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के तौर मनाने का भी जिक्र किया। संसदीय दल की बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि बैठक में वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के प्रयोग को लेकर प्रजेंटेशन दिया गया। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने चुनाव सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक (जो सोमवार को लोक सभा से पारित हुआ था) के बारे में सांसदों को बताया। मेघवाल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में खास तौर से स्वस्थ्य बाल— बालिका स्पर्धा का जिक्र करते हुए सभी सांसदों को इसे अपने—अपने क्षेत्र में करने को कहा है। उन्होंने सांसदों का आह्ववान करते हुए कहा कि देश भर में अभी भी 6 करोड़ 27 लाख पात्र बच्चे आंगनवाड़ी से नहीं जुड़े हुए हैं। सांसदों को इन सभी बच्चों को आंगनवाड़ी कार्यक्रम से जोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी सांसदों को संगठन से जुड़ने की भी नसीहत दी। भाजपा लोक सभा सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती , 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में बढ़—चढ़ कर मनाने , बजट सत्र से पहले सभी सांसदों को सांसद खेल स्पर्धा संपन्न करवा लेने और संगठन के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में रहने का निर्देश दिया। बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक हुए विधायी कार्यो और शेष बचे हुए दिनों में जिन विधेयकों को पारित करवाना है, उसे लेकर भी चर्चा हुई। संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा संसदीय दल की यह दूसरी बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य सभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल , कानून मंत्री किरेन रिजिजू के साथ – साथ सरकार के कई अन्य मंत्री और भाजपा के लोक सभा और राज्य सभा के सांसद भी शामिल हुए।

अवध की आवाज हिन्दी दैनिक, प्रकाशक ,मुद्रक व स्वामी,अनिल कुमार सिंह द्वारा स्काई लाइन प्रिन्टर्स,119/23 खन्दारी लेन, लालबाग, लखनऊ उ0प्र0 से मुद्रित तथा डी—97/3 व 7,सेक्टर—7, इन्दिरा नगर,लखनऊ,उ0प्र0 से प्रकाशित। सम्पादक अनिल कुमार सिंह फोन : 0522—4340954
मो0—7905407289, Email: avadhkiaawaz@gmail.com
R.N.I.- UPHIN/2012/45127
नोट : समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादोंका न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।